



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2017/वैशाख 19, 1939

No. 357]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2017/VAISAKHA 19, 1939

इस्पात मंत्रालय

(स्थापना प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2017

सा.का.नि. 451(अ).—सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों को वरीयता देने की नीति सामान्य जानकारी हेतु एतद्वारा प्रकाशित की जाती है :-

सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों को वरीयता देने के लिए नीति

1. पृष्ठभूमि

- 1.1 यह नीति सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी) को वरीयता देती है।
- 1.2 यह नीति यथा लागू निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुपालन में परिशिष्ट-क में यथा दिए गए अनुसार उत्पादित लोहा एवं इस्पात उत्पादों पर लागू होती है।
- 1.3 यह नीति सरकारी परियोजनाओं के लिए लोहा एवं इस्पात उत्पादों की खरीद के लिए प्रत्येक मंत्रालय अथवा सरकार के विभाग और उनके प्रशासनिक नियंत्रण में सारी एजेंसियों अथवा प्रतिष्ठानों पर और न कि वाणिज्यिक पुनर्विक्री के उद्देश्य अथवा वाणिज्यिक बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग के उद्देश्य लागू है।

2. परिभाषा

- i. बोली लगाने वाला इस्पात का घरेलू/विदेशी निर्माता अथवा उसका बिक्री एजेंट/अधिकृत वितरक/अधिकृत डीलर/अधिकृत आपूर्ति गृह अथवा किसी अन्य कंपनी, जो सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई निधियों वाली परियोजनाओं की बोली लगाने में लगा हुआ हो, हो सकता है।
- ii. "घरेलू रूप से निर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी)" वे लोहा एवं इस्पात उत्पाद हैं जिनका निर्माण उन प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सहित भारत में पंजीकृत अथवा स्थापित हैं। इसके अलावा, ऐसे उत्पाद परिशिष्ट-क में यथा उल्लिखित घरेलू न्यूनतम मूल्य संवर्धन के मानदंड को पूरा करेंगे।

- iii. घरेलू विनिर्माता, घरेलू रूप से विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी) का एक विनिर्माता है।
- iv. इस नीति के उद्देश्य के लिये सरकार का आशय भारत सरकार से है।
- v. सरकारी एजेंसियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सोसायटी, ट्रस्ट और सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय शामिल हैं।
- vi. इस्पात मंत्रालय का आशय इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से है।
- vii. निवल बिक्री कीमत एक्स-वर्क्स/एक्स-फैक्ट्री कीमत होगी जिसमें संयंत्र में आयात किए गए इस्पात का पहुँच मूल्य तथा सभी अन्य लागत संघटक, जो निवेश पर मामूली आय को शामिल करते हुए परिवर्तन लागत का हिस्सा हैं, होगी। यह कीमत एक्स-फैक्ट्री में लागू किसी शुल्क और करों को छोड़कर है।
- viii. अर्ध तैयार इस्पात से आशय बिलेट, ब्लूम, स्लैब (कास्ट उत्पाद), जिसे बाद में तैयार इस्पात के लिए प्रसाधित किया जा सकता है, से है।
- ix. तैयार इस्पात से आशय फ्लैट और लांग उत्पाद से है जिसे बाद में प्रसाधित कर निर्मित मदें बनाई जाती हैं।
- x. लोहा एवं इस्पात उत्पाद का आशय ऐसे इस्पात एवं लोहा उत्पादों से है जिनका उल्लेख परिशिष्ट-क में किया गया है।

3. बाह्यकरण:

ऐसे सभी सरकारी खरीदों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट दी जाएगी:

- क) जहां इस्पात की विशिष्ट ग्रेडों का निर्माण देश में नहीं किया जाता हो अथवा
- ख) जहां परियोजना की मांग के अनुसार मात्राओं को घरेलू स्रोतों के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है।

4. स्थायी समिति:

इस्पात मंत्रालय (एमओएस) के अधीन सचिव की अध्यक्षता वाली एक स्थायी समिति का गठन इस नीति के कार्यान्वयन का कार्य देखने के लिए किया जाएगा। इस समिति में उद्योग/उद्योग संघ/सरकारी संस्थान अथवा निकाय/इस्पात मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस्पात मंत्रालय में उक्त समिति के पास निम्नलिखित अधिकार होगा:

- क) इस नीति के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग
- ख) लोहा एवं इस्पात उत्पादों तथा परिशिष्ट-क में उल्लिखित न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंडों की समीक्षा करना और उसे अधिसूचित करना।
- ग) खरीद एजेंसियों को पैरा 3 के अनुसार छूट देने सहित इस नीति के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करना।
- घ) शिकायत समाधान के लिए एक अलग समिति गठित करना
- ङ) यह स्थायी समिति अपनी सिफारिशें अनुमोदन हेतु इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

5. सरकार द्वारा खरीदे गए लोहा एवं इस्पात उत्पादों को अधिसूचित करना

5.1 निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का इस नीति के अंतर्गत ऊपर उल्लिखित उत्पादों की पहचान करने तथा उसे अधिसूचित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है:

- (a) इस नीति का उद्देश्य सभी लोहा एवं इस्पात उत्पादों को अधिसूचित करना है जिनकी खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा सरकारी परियोजनाओं के लिए किया जाता है और यह वाणिज्यिक रूप से फिर बिक्री करने अथवा वाणिज्यिक बिक्री के उत्पादों के उत्पादन में उपयोग करने के उद्देश्य से की गई खरीद के लिए नहीं है।
- (b) केवल लोहा एवं इस्पात उत्पादों, जिनका सकल अनुमानित मूल्य 50 करोड़ और अधिक भारतीय रुपए है और जो इस्पात गहन परियोजना अथवा समग्र परियोजना का अधिक हिस्सा बनता हो, को इस नीति के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- (c) घरेलू लोहा एवं इस्पात उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों की उपलब्धता का विश्लेषण इस नीति के अंतर्गत अधिसूचना के पूर्व किए जाने की आवश्यकता है। केवल उन लोहा एवं इस्पात उत्पादों, जिसके संबंध में कम से कम एक घरेलू निर्माता हो, को अधिसूचित किया जाएगा। स्थायी समिति द्वारा परामर्श किया जा सकता है।

5.2 इस्पात मंत्रालय (एमओएस) परिशिष्ट-क में दिए गए न्यूनतम निर्धारित मूल्य संवर्धन के साथ-साथ लोहा एवं इस्पात उत्पादों के अधिसूचित करेगा। परिशिष्ट-क की समीक्षा स्थायी समिति द्वारा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाएगा।

5.3 सरकारी एजेंसियां, जो सरकारी परियोजनाओं में लोहा एवं इस्पात उत्पादों की खरीद में शामिल हैं और यदि ऐसे उत्पाद का उल्लेख परिशिष्ट-क में नहीं किया गया तो वे स्थायी समिति को निर्धारित मानदंडों के साथ-साथ इस उत्पाद का विवरण एवं तकनीकी विनिर्देशन प्रदान करेगा। स्थायी समिति पैरा 4 में दिए गए अधिकार के अनुसार कार्य करेगी।

5.4 मूल्य संवर्धन संबंधी मानदंड को इस तरह से निर्धारित किया जाएगा कि यह किसी समय विशेष में लोहा एवं इस्पात उत्पादों के लिए घरेलू उद्योग की औसत/औसत से अधिक निर्माण क्षमता को दर्शाता हो। इसकी उपयुक्त रूप से इस नीति के अनुसार समीक्षा की जाएगी।

6. सरकार एवं सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया

6.1 खरीदने वाली सरकारी एजेंसियां डीएमआई एंड एसपी को वरीयता देते समय वित्त मंत्रालय एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों के अनुसार मानक खरीद प्रक्रिया का पालन करेगी। सभी निविदाओं के मामले में, जहां कीमत बोलियां नहीं खोली गई हैं, यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

6.2 निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से बोली लगाने वाले द्वारा न्यूनतम निर्धारित घरेलू मूल्य संवर्धन (जैसा कि परिशिष्ट-क में दर्शाया गया है) का पालन करने के लिए स्पष्ट अर्हता मानदंड का उल्लेख किया जाएगा, वशर्ते लोहा एवं इस्पात उत्पादों की की गई खरीद का अनुमानित मूल्य 50 करोड़ भारतीय रूपए अथवा उससे अधिक हो और जो इस्पात गहन परियोजना अथवा समग्र परियोजना का हिस्सा बनता हो।

6.3 बोली लगाने वाले, जो लोहा एवं इस्पात उत्पादों के घरेलू निर्माता का एकमात्र बिक्री करने वाले एजेंट/अधिकृत वितरक/अधिकृत डीलर/अधिकृत आपूर्ति गृह हैं, इस नीति के अंतर्गत घरेलू निर्माताओं की ओर से बोली लगाने के लिए पात्र हैं। हालांकि, यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

- (a) बोली लगाने वाला घरेलू रूप से निर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों की बिक्री के लिए घरेलू विनिर्माता द्वारा जारी की प्राधिकृत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (b) बोली लगाने वाला घरेलू उद्योग द्वारा जारी स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र खरीदने वाली एजेंसी को यह घोषित करते हुए प्रस्तुत करेगा कि लोहा एवं इस्पात उत्पाद निर्धारित घरेलू मूल्य संवर्धन के संबंध में घरेलू रूप से निर्मित हैं।
- (c) यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह इस नीति के अनुसार, खरीदने वाली एजेंसी को घरेलू विनिर्माता द्वारा जारी किए जाने वाले अपेक्षित अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।

7. मूल्य वर्धन

7.1 भारत में निर्माण संयंत्र पर आयात की गई इनपुट इस्पात (तत्काल पूर्व प्रक्रिया का) की पहुँच कीमत और निवल बिक्री कीमत के बीच मूल्य संवर्धन अंतर होगा।

7.2 यदि लोहा एवं इस्पात उत्पाद निम्नलिखित का उपयोग करते हुए बनाए गए हैं—

- क) घरेलू इनपुट इस्पात (अर्ध तैयार/तैयार इस्पात) का उपयोग करते हुए, खरीदी गई मात्रा के साथ-साथ वास्तविक घरेलू उत्पादकों से खरीद का बीजक एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों को खरीद करने वाली सरकारी एजेंसी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ख) आयात किए गए और घरेलू इनपुट इस्पात के मिश्रण का उपयोग करते हुए, खरीदी गई मात्राओं के साथ-साथ वास्तविक उत्पादकों से खरीद का बीजक तथा अन्य संबंधित दस्तावेज अलग-अलग प्रस्तुत किए जाने चाहिए। घरेलू मूल्य संवर्धन की सीमा निकालने के लिए, इनपुट इस्पात (आयात किए गए एवं घरेलू) दोनों का भारित औसत पर विचार यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि इस नीति की न्यूनतम निर्धारित घरेलू मूल्य संवर्धन आवश्यकता का पालन किया गया है।
- ग) केवल आयात किए गए इनपुट इस्पात का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित फॉर्मूला घरेलू मूल्य वर्धक के प्रतिशत की गणना करने के लिए लागू होगा :

$$\text{घरेलू मूल्य संवर्धन (\%)} = (\text{निवल बिक्री कीमत-संयंत्र में आयातित इनपुट इस्पात का पहुँच मूल्य}) * 100 / (\text{संयंत्र में आयातित इनपुट इस्पात का पहुँच मूल्य})$$

यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक बोली लगाने वाले, जो निविदा की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, को यह सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त फॉर्मले का उपयोग करते हुए घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना करनी चाहिए ताकि दावा किया गया घरेलू मूल्य संवर्धन इस नीति की न्यूनतम निर्धारित घरेलू मूल्य संवर्धन की अपेक्षा के अनुरूप हो।

8. स्व-प्रमाणन

- 8.1 प्रत्येक घरेलू विनिर्माता को खरीद करने वाली सरकारी एजेंसी को यह घोषित करते हुए स्व-प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि लोहा एवं इस्पात उत्पादों का निर्धारित घरेलू मूल्य संवर्धन का घरेलू रूप से निर्माण किया गया है। बोली लगाने वाले, जो लोहा एवं इस्पात उत्पादों के घरेलू निर्माण का एकमात्र विक्री करने वाले एजेंट/अधिकृत वितरक/अधिकृत डीलर/अधिकृत आपूर्ति गृह हैं, इस नीति के अंतर्गत घरेलू निर्माताओं की ओर से बोली लगाने के लिए पात्र हैं। बोली लगाने वाला घरेलू विनिर्माता खरीद करने वाली सरकारी एजेंसी को यह घोषित करते हुए स्व-प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि लोहा एवं इस्पात उत्पादों का निर्धारित घरेलू मूल्य संवर्धन का घरेलू रूप से निर्माण किया गया है। स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र इन दिशा-निर्देशों के साथ संलग्न फॉर्म-1 में प्रस्तुत किया जाएगा।
- 8.2 घरेलू विनिर्माता की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि इस प्रकार से दावा किए गए उत्पाद इस उत्पाद के लिए निर्धारित घरेलू मूल्य संवर्धन के संबंध में डीएमआई एंड एसपी है। बोली लगाने वाले से यह भी अपेक्षित होगा कि वह घरेलू विनिर्माता की सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत सत्यापित छमाही आधार (30 सितंबर और 31 मार्च) पर यह मूल्य संवर्धन प्रमाण-पत्र भी प्रदान करेगा कि पिछले छः महीनों के दौरान इस उत्पाद के लिए दावे इस नीति के अनुसार हैं। इस प्रकार के प्रमाण-पत्र संबंधित सरकारी एजेंसियों को प्रत्येक छमाही के शुरू होने के 60 दिनों के भीतर दायर किया जाएगा और उपरोक्त उत्पादों की आपूर्ति पूर्ण होने तक दायर किया जाता रहेगा।
- 8.3 खरीदने वाली एजेंसी बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत इस्पात उत्पाद में घरेलू मूल्य संवर्धन के संबंध में स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र स्वीकार करेगी। खरीद करने वाली एजेंसी की सामान्य रूप से यह जिम्मेदारी नहीं होगी कि वह इस दावे की सत्यता का सत्यापन करे। उसके सत्यापन को दर्शाने की जिम्मेदारी बोली लगाने पर होगी, जब उसे ऐसा कहने के लिए कहा जाए।
- 8.4 यदि खरीदने वाली एजेंसी अथवा संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा लोहा एवं इस्पात उत्पादों में घरेलू मूल्य संवर्धन के संबंध में किसी बोली लगाने वाले के दावे के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तब खरीदने वाली एजेंसी के पास सभी संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने और उसकी जांच करने तथा निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा। यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, तब यह मामला इस्पात मंत्रालय को तकनीकी सहायता के अनुरोध के साथ भेजा जा सकता है।
- 8.5 सरकारी एजेंसी को संदर्भित किसी शिकायत का निपटारा सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ 4 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। बोली लगाने वाले से यह अपेक्षित होगा कि वह शिकायत दायर करने के दो सप्ताह के भीतर सरकारी एजेंसी को लोहा एवं इस्पात उत्पादों में दावा किए गए घरेलू मूल्य संवर्धन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे।
- 8.6 यदि इस मामले को इस्पात मंत्रालय को भेजा जाता है, तब इस्पात मंत्रालय के अधीन स्थापित शिकायत निवारण समिति सरकारी एजेंसी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखने के बाद, बोली लगाने वाले से सभी दस्तावेजों को भेजे जाने तथा प्राप्त होने के 4 सप्ताह के भीतर शिकायत का निपटारा करेगी। बोली लगाने वाले से यह अपेक्षित होगा कि वह इस मामले को भेजे जाने के 2 सप्ताह के भीतर इस्पात मंत्रालय के अधीन शिकायत निवारण समिति को लोहा एवं इस्पात उत्पादों में दावा किए गए घरेलू मूल्य संवर्धन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे। यदि बोली लगाने वाले द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है, तब शिकायत निवारण समिति आगे इस दावे की सत्यता स्थापित करने के लिए सरकारी एजेंसी के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।
- 8.7 यदि घरेलू मूल्य संवर्धन प्रमाण-पत्र के अनुसार सही पाया जाता है, तब घरेलू मूल्य संवर्धन की निर्धारित सीमा का आकलन करने की लागत को खरीद करने वाली एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि, यदि यह पाया जाता है कि दावा किए गए अनुसार घरेलू मूल्य संवर्धन सही नहीं है तब आकलन की लागत उस बोली लगाने वाले द्वारा देय होगी जिसने गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है। उसे लागू करने के तरीके को निविदा दस्तावेज में परिभाषित किया जाएगा।
- 8.8 निविदा दस्तावेज में निर्धारित घरेलू मूल्य संवर्धन की बोली लगाने वाले द्वारा गलत घोषणा की स्थिति में प्रत्येक सरकारी एजेंसी स्पष्ट रूप से दंड को परिभाषित करेगा। इन दंडों में बयाना जमा राशि जब्त करने तथा ऐसे अन्य दंड शामिल होंगे, जिन्हें निविदा दस्तावेज में संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- 8.9 संबंधित बोली लगाने वाले द्वारा इस्पात मंत्रालय को कोई शिकायत भेजे जाने की स्थिति में, खरीदी जा रही डीएमआई एंड एसपी के मूल्य के 0.2 प्रतिशत अथवा 10 लाख रुपए के शिकायत शुल्क (20 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्याधीन), इसमें से जो भी अधिक हो, लगाई जाएगी, जिसका भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ-साथ इस्पात मंत्रालय के अधीन शिकायत निवारण समिति के पास डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाएगा। यदि शिकायत को गलत पाया जाए तब सरकारी एजेंसी के पास उक्त राशि को जब्त करने का अधिकार रहेगा। यदि शिकायत पर्याप्त रूप से सही पाई जाए तब शिकायतकर्ता की जमा की गई शुल्क राशि को बिना किसी ब्याज के लौटाया जाएगा।

9. मॉनीटरिंग

9.1 इस्पात मंत्रालय इस नीति के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा।

9.2 प्रत्येक सरकारी एजेंसी इस नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी और वार्षिक रूप से जून के महीने में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस नीति के अनुपालन की सीमा और इसके अनुपालन नहीं करने के कारणों का उल्लेख करते हुए एक घोषणा पत्र भेजेगी।

10. इस्पात मंत्रालय को संदर्भ

यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या खरीदी जा रही कोई मद डीएमआई एंड एसपी है जिसे इस नीति के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, यह मामला स्पष्टीकरण के लिए इस्पात मंत्रालय को भेजा जाएगा।

[फा. सं. II (34)/2015-आईडीडी]

सय्यदेन अब्बासी, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-क

लोहा एवं इस्पात उत्पादों की सूची
(पैरा 7.2 का संदर्भ देखें)

क्रम सं.	लोहा एवं इस्पात उत्पाद	इनपुट (आयात और घरेलू)	न्यूनतम मूल्य संवर्धन
1	डक्टाइल आयरन पाइप	कच्चा लौह/तरल लोहा	15%
2	वायर रॉड और टीएमटी बार	बिलेट	15%
3	स्ट्रक्चरल्स/सेक्शन	ब्लूम	15%
4	एचआर कॉइल्स, स्ट्रिप्स, शीट्स और प्लेट्स	स्लैब	15%
5	एचआर यूनिवर्सल/क्वार्टो प्लेट्स	स्लैब	15%
6	सीआर कॉइल्स/स्ट्रिप्स	एचआर कॉइल्स	15%
7	कोटेड फ्लैट इस्पात उत्पाद/जीपी/जीसी शीट्स/एआई-जिंक कोटेड	स्लैब/एचआर कॉइल/कोल्ड रोलड कॉइल/स्ट्रिप्स	15%
8	क्लर कोटेड, पेंटेड शीट्स	स्लैब/एचआर कॉइल/कोल्ड रोलड कॉइल/स्ट्रिप्स	15%
9	इस्पात पाइप और ट्यूब सभी प्रकार के	स्लैब/प्लेट्स/एचआर कॉइल्स	15%
10	सीमलेस ट्यूब और पाइप	ब्लूम	15%
11	रेल्स	ब्लूम	15%

फॉर्म-1

लोहा एवं इस्पात उत्पादों में घरेलू मूल्य संवर्धन के संबंध में दिए जाने वाला 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र के लिए प्रपत्र

दिनांक:

मैं _____ सुपुत्र, _____ सुपुत्री, _____ धर्मपत्नी, _____ निवासी
_____ एतद्वारा निम्नलिखित वचन देता/देती तथा घोषित

करता/करती हूँ:

कि मैं अधिसूचना संख्या _____ के माध्यम से जारी भारत सरकार की नीति की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत होऊंगा/होऊंगी।

कि इसमें प्रस्तुत सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है और मैं घरेलू मूल्य संवर्धन का आकलन करने के उद्देश्य से खरीद करने वाली एजेंसी के समक्ष संगत अभिलेख प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ।

कि सभी इनपुट, जो उक्त लोहा एवं इस्पात उत्पाद हैं, का घरेलू मूल्य संवर्धन का सत्यापन मेरे द्वारा कर लिया गया है और मैं इसमें किए गए दावों की सत्यता के लिए जिम्मेदार हूँ।

कि इसमें उल्लिखित उत्पाद के घरेलू मूल्य संवर्धन सही नहीं पाए जाने की स्थिति में और घरेलू मूल्य संवर्धन का आकलन करने के उद्देश्य से खरीद करने वाली एजेंसी के आकलन के आधार पर निर्धारित मूल्य संवर्धन मानदंड को पूरा नहीं करने की स्थिति में मुझे किसी सरकारी

निविदा से 36 महीने की अवधि के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा। इसके अलावा मैं इस प्रकार के आकलन के लिए सभी लागतों का वहन करूंगा/करूंगी।

कि मैंने अधिसूचना संख्या _____ में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन कर लिया है जिसमें सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों को वरीयता दी गई है और खरीदने वाली एजेंसी एतद्वारा मेरे जमा बयाना राशि जम्मा करने के लिए अधिकृत है। मैं निविदा दस्तावेज़ में यथा विनिर्दिष्ट आकलन लागत और सभी दंडों का भी भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं 8 वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के अभिलेख में निम्नलिखित सूचना रखने के लिए सहमत हूँ और किसी सांविधिक प्राधिकारी को सत्यापन के लिए इसे उपलब्ध कराऊंगा/कराऊंगी:

i. बोली लगाने वाले का नाम और विवरण

(पंजीकृत कार्यालय, विनिर्माण इकाई का पता, कानूनी प्रतिष्ठान की प्रकृति)

ii. वह तिथि जब यह प्रमाण-पत्र जारी किया गया

iii. लोहा एवं इस्पात उत्पाद जिनके लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है

iv. खरीदने वाली एजेंसी जिसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है

v. दावा किए गए घरेलू मूल्य संवर्धन का प्रतिशत और क्या यह निर्धारित घरेलू मूल्य संवर्धन के सीमा मूल्य को पूरा करता है

vi. विनिर्माता इकाई का नाम और संपर्क व्यौरे

vii. लोहा एवं इस्पात उत्पादों की निवल बिक्री कीमत

viii. संयंत्र तक भाड़ा, बीमा और रख-रखाव

ix. लोहा एवं इस्पात उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रयोग किए गए इनपुट इस्पात (आयातित) की सूची एवं कुल लागत मूल्य

x. घरेलू रूप से लिए गए इनपुट इस्पात की सूची एवं कुल लागत

xi. कृपया आपूर्तिकर्ताओं से मूल्य संवर्धन प्रमाण-पत्र, यदि इनपुट नहीं हो, संलग्न करें

xii. आयात किए गए इनपुट इस्पात के लिए, सीआईएफ मूल्य, शुल्क एवं कर, पत्तन रख-रखाव शुल्क और अंतर्देशीय भाड़ा लागत के व्यौरे के साथ भारतीय पत्तन पर पहुँचने तक लागत

_____ (फर्म/प्रतिष्ठान का नाम) के लिए और उसकी ओर से

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत)

<नाम, पदनाम और संपर्क सं. का उल्लेख करें>

MINISTRY OF STEEL (ESTABLISHMENT DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2017

G.S.R. 451(E).—The Policy for providing preference to domestically manufactured Iron & Steel products in Government procurement is hereby published for general information.:—

POLICY FOR PROVIDING PREFERENCE TO DOMESTICALLY MANUFACTURED IRON & STEEL PRODUCTS IN GOVERNMENT PROCUREMENT

1. Background

- 1.1 This policy provides preference to Domestically Manufactured Iron and Steel Products (DMI&SP) in Government procurement.
- 1.2 The policy is applicable to iron & steel products as provided in Appendix A, produced in compliance to prescribed quality standards, as applicable.
- 1.3 The policy is applicable to every Ministry or Department of Government and all agencies/entities under their administrative control for purchase of iron & steel products for government projects and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale.

2. Definition

- i. **Bidder** may be a domestic/ foreign manufacturer of steel or their selling agents/ authorized distributors/ authorized dealers/ authorized supply houses or any other company engaged in the bidding of projects funded by Government agencies.
- ii. **"Domestically Manufactured Iron & Steel Products (DMI&SP)"** are those iron and steel products which are manufactured by entities that are registered and established in India, including in Special Economic Zones (SEZs). In addition, such products shall meet the criteria of domestic minimum value-addition as mentioned in Appendix-A.

- iii. **Domestic Manufacturer** is a manufacturer of domestically manufactured iron & steel products (DMI&SP).
- iv. **Government** for the purpose of the Policy means Government of India.
- v. **Government agencies** include Government PSUs, Societies, Trusts and Statutory bodies set up by the Government.
- vi. **MoS** shall mean Ministry of Steel, Govt. of India.
- vii. **Net Selling Price** shall be the Ex-works/Ex-factory price comprising of the landed cost of imported steel at the plant and all other cost elements forming part of the conversion cost inclusive of nominal return on investment. This price is exclusive of any duties and taxes applicable ex-factory.
- viii. **Semi-Finished Steel** shall mean billet, blooms, slabs (cast products), which can be subsequently processed to finished steel.
- ix. **Finished Steel** shall mean Flat and Long products, which can be subsequently processed into manufactured items.
- x. **Iron & Steel Product(s)** shall mean such iron and steel product (s) which are mentioned in Appendix A.

3. Exclusions:

Waivers shall be granted to all such Government procurements subject to following conditions:

- a. where specific grades of steel are not manufactured in the country, or
- b. where the quantities as per the demand of the project cannot be met through domestic sources

4. Standing Committee:

A Standing Committee under the Ministry of Steel (MoS) to be chaired by the Secretary (Steel), shall be constituted to oversee the implementation of the policy. The Committee shall comprise of experts drawn from Industry/Industry Association/Government Institution or Body/Ministry of Steel (MoS). The said Committee in MoS shall have the mandate for the following:

- a. Monitoring the implementation of the policy
- b. Review and notify the list of Iron & Steel products and the Minimum value addition criterion as mentioned at Appendix-A
- c. Issue necessary clarifications for implementation of the policy including grant of exclusions to procuring agencies as per para 3
- d. Constitute a separate committee to carry out Grievance redressal
- e. The Standing Committee shall submit its recommendations for approval to Ministry of Steel.

5. Notifying Iron & Steel Products Procured by Government

- 5.1 The following guidelines may be used for identifying and notifying the aforementioned products under the policy :-
 - (a) The objective of the policy is to notify all iron & steel products which are procured by Government Agencies for government projects and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of products for commercial sale.
 - (b) Only iron & steel products having aggregated estimate value of INR 50 Crores and more forming part of the steel intensive project or overall project, shall be covered under the policy.
 - (c) Analysis of the availability of various grades of domestic iron and steel products needs to precede for notification under the policy. Only those iron & steel products, in respect of which at least one domestic manufacturer exists, shall be notified. Consultation may be carried out by the Standing Committee.
- 5.2 The Ministry of Steel (MoS) would notify iron & steel products along with the minimum prescribed value addition, furnished at Appendix-A. The Appendix-A will be reviewed by the Standing Committee and amended, if required with the approval of competent authority.
- 5.3 Government agencies which are involved in procurement of iron and steel products in government projects and if such product is not mentioned in Appendix-A, they will provide description and technical specifications of the product alongwith prescribed standards to the Standing Committee. The Standing Committee will act as per the mandate at para 4.

5.4 The value addition norm shall be so calibrated that it reflects the average/ above average manufacturing capability of the domestic industry for the iron & steel products at a point of time. This shall be suitably reviewed as per the policy.

6. Tender Procedure for Procurement by Government and Government Agencies

- 6.1 The procuring/ Government agencies shall follow standard procurement procedures, in accordance with instructions of Ministry of Finance and CVC while providing preference to DMI&SP. The policy shall come into effect from the date of its notification in all tenders where price bid have not been opened.
- 6.2 The tender document should explicitly outline the qualification criteria for adherence to minimum prescribed domestic value addition by the bidder (as indicated at Appendix-A), provided there is procurement of iron & steel products having estimated value of INR 50 Crores or more, forming part of the steel intensive project or overall project.
- 6.3 The bidders who are sole selling agents /authorized distributors /authorized dealers /authorized supply houses of the domestic manufacturers of iron & steel products are eligible to bid on behalf of the domestic manufacturers under the policy. However, this shall be subject to the following conditions:
 - a. The bidder shall furnish the authorization certificate issued by the domestic manufacturer for selling domestically manufactured iron & steel products.
 - b. The bidder shall furnish the Affidavit of self-certification issued by the domestic manufacturer to the procuring agency declaring that the iron & steel products is domestically manufactured in terms of the domestic value addition prescribed.
 - c. It shall be the responsibility of the bidder to furnish other requisite documents required to be issued by the domestic manufacturer to the procuring agency as per the policy.

7 Value addition

- 7.1 Value addition shall be the difference between the net selling price and the landed cost of imported input steel (of immediate prior process) at a manufacturing plant in India.
- 7.2 In case, the iron & steel products are made –
 - a. Using domestic input steel (semi-finished/ finished steel), invoices of purchases from the actual domestic producers along with quantities purchased and the other related documents must be furnished to procuring Government agency.
 - b. Using a mix of imported and domestic input steel, the invoices of purchases from the actual producers along with quantities purchased and the other related documents must be furnished separately. To derive the extent of domestic value addition, the weighted average of both (imported & domestic) input steel shall be considered to ensure that the minimum stipulated domestic value addition requirement of the policy is complied with.
 - c. Using only imported input steel, the following formula shall apply to calculate the percentage of domestic value-addition:

Domestic value addition (%) = $\frac{\text{Net selling price} - \text{Landed cost of imported input steel at the plant}}{\text{Landed cost of imported input steel at the plant}} \times 100$

It is recommended that each bidder participating in the tender process should calculate the domestic value-addition using the above formulae so as to ensure the domestic value addition claimed is consistent with the minimum stipulated domestic value addition requirement of the policy.

8 Self-Certification

- 8.1 Each domestic manufacturer shall furnish the Affidavit of self-certification to the procuring Government agency declaring that the iron & steel products are domestically manufactured in terms of the domestic value addition prescribed. The bidders who are sole selling agents/authorized distributors/authorized dealers/authorized supply houses of the domestic manufacturers of iron & steel products are eligible to bid on behalf of domestic manufacturers under the policy. The bidder shall furnish the Affidavit of self-certification issued by the domestic manufacturer to the procuring agency declaring that the iron & steel products are domestically manufactured in terms of the domestic value addition prescribed. The Affidavit of self-certification shall be furnished in **Form 1** attached to these guidelines.
- 8.2 It shall be the responsibility of the domestic manufacturer to ensure that the products so claimed are DMI&SP in terms of the domestic value addition prescribed for the product. The bidder shall also be required to provide a value- addition certificate on half-yearly basis (Sep 30 and Mar 31), duly certified by the Statutory Auditors of the domestic manufacturer, that the claims of value-addition made for the product during the preceding 6 months are in accordance with the Policy. Such certificate shall be filed within 60 days of commencement of each half

year, to the concerned Government agencies and shall continue to be filed till the completion of supply of the said products.

- 8.3 The procuring agency shall accept the Affidavit of self-certification regarding domestic value addition in a steel product submitted by a bidder. It shall not normally be the responsibility of procuring agency to verify the correctness of the claim. The onus of demonstrating the correctness of the same shall be on the bidder when asked to do so.
- 8.4 In case a complaint is received by the procuring agency or the concerned Government Agency against the claim of a bidder regarding domestic value addition in iron & steel products, the procuring agency shall have full rights to inspect and examine all the related documents and take a decision. In case any clarification is needed, matter may be referred to MoS with a request for technical assistance.
- 8.5 Any complaint referred to the Government Agency shall be disposed off within 4 weeks of the reference along with submission of all necessary documents. The bidder shall be required to furnish the necessary documentation in support of the domestic value addition claimed in iron & steel products to the Government Agency within 2 weeks of filing the complaint.
- 8.6 In case, the matter is referred to the Ministry of Steel, the grievance redressal committee setup under the MoS shall dispose off the complaint within 4 weeks of its reference and receipt of all documents from the bidder after taking in consideration, the view of the Government Agency. The bidder shall be required to furnish the necessary documentation in support of the domestic value addition claimed in iron & steel products to the grievance redressal committee under MoS within 2 weeks of the reference of the matter. If no information is furnished by the bidder, the grievance redressal committee may take further necessary action, in consultation with Government Agency to establish the bonafides of the claim.
- 8.7 The cost of assessing the prescribed extent of domestic value addition shall be borne by the procuring agency if the domestic value addition is found to be correct as per the certificate. However, if it is found that the domestic value addition as claimed is incorrect, the cost of assessment will be payable by the bidder who has furnished an incorrect certificate. The manner of enforcing the same shall be defined in the tender document.
- 8.8 Each Government Agency shall clearly define the penalties, in case of mis-declaration by the bidder of the prescribed domestic value addition, in the tender document. The penalties may include forfeiting of the EMD and such other penalties, as may be prescribed by the concerned Government Agency in the tender document.
- 8.9 In case of reference of any complaint to MoS by the concerned bidder, there would be a complaint fee of Rs. 10 Lakh or 0.2 % of the value of the DMI&SP being procured (subject to a maximum of Rs. 20 Lakh), whichever is higher, to be paid by Demand Draft deposited with the grievance redressal committee under MoS along with the complaint by the complainant. In case, the complaint is found to be incorrect, the Government Agency reserves the right to forfeit the said amount. In case, the complaint is found to be substantially correct, deposited fee of the complainant would be refunded without any interest.

9 Monitoring

- 9.1 MoS shall be the nodal ministry to monitor the implementation of the policy.
- 9.2 Every Government Agency shall ensure implementation of the policy and shall annually, in the month of June, send a declaration indicating the extent of compliance to the policy and reasons for non-compliance thereof, during the preceding financial year.

10 Reference to Ministry of Steel

In case of a question whether an item being procured is a DMI&SP to be covered under the policy, the matter would be referred to the Ministry of Steel for clarification.

[F. No. 11(34)/2015-IDD]

SYEDAIN ABBASI, Jt. Secy.

Appendix-A

List of Iron & Steel Products (Refer Para 7.2)

Sl. No	Iron & Steel Products	Inputs (Imported or Domestic)	Minimum Value Addition
1	Ductile Iron Pipe	Pig Iron/Liquid Iron	15%
2	Wire rod & TMT bar	Billet	15%

3	Structural/sections	Bloom	15%
4	HR Coils, strips, sheets & plates	Slab	15%
5	HR universal/Quarto Plates	Slab	15%
6	CR coils/strips	HR coils	15%
7	Coated flat steel products/ GP/GC sheets/ Al-Zn coated	Slab/ HR Coil/ Cold rolled coils/strips	15%
8	Color coated, painted sheets	Slab/ HR Coil/ Cold rolled coils/strips	15%
9	All kinds of steel pipes & tubes	Slabs/ Plates/ HR coils	15%
10	Seamless tubes & pipes	Bloom	15%
11	Rails	Bloom	15%

Form-1

Format for Affidavit of Self Certification regarding Domestic Value Addition in Iron & Steel Products to be provided on Rs.100/- Stamp Paper

Date:

I _____ S/o, _____ D/o, _____ W/o, _____ Resident of _____ hereby solemnly affirm and declare as under:

That I will agree to abide by the terms and conditions of the policy of Government of India issued vide Notification No: _____.

That the information furnished hereinafter is correct to the best of my knowledge and belief and I undertake to produce relevant records before the procuring agency (ies) for the purpose of assessing the domestic value addition.

That the domestic value addition for all inputs which constitute the said iron & steel products has been verified by me and I am responsible for the correctness of the claims made therein.

That in the event of the domestic value addition of the product mentioned herein is found to be incorrect and not meeting the prescribed value-addition criteria, based on the assessment of procuring agency (ies) for the purpose of assessing the domestic value-addition, I will be disqualified from any Government tender for a period of 36 months. In addition, I will bear all costs of such an assessment.

That I have complied with all conditions referred to in the Notification No. _____ wherein preference to domestically manufactured iron & steel products in Government procurement is provided and that the procuring agency (ies) is hereby authorized to forfeit and my EMD. I also undertake to pay the assessment cost and pay all penalties as specified in the tender document.

I agree to maintain the following information in the Company's record for a period of 8 years and shall make this available for verification to any statutory authority.

- i Name and details of the Bidder
(Registered Office, Manufacturing unit location, nature of legal entity)
- ii. Date on which this certificate is issued
- iii. Iron & Steel Products for which the certificate is produced
- iv. Procuring agency to whom the certificate is furnished
- v. Percentage of domestic value addition claimed and whether it meets the threshold value of domestic value addition prescribed
- vi. Name and contact details of the unit of the manufacturer (s)
- vii. Net Selling Price of the iron & steel products
- viii. Freight, insurance and handling till plant
- ix. List and total cost value of input steel (imported) used to manufacture the iron & steel products
- x. List and total cost of input steel which are domestically sourced.
- xi. Please attach value addition certificates from suppliers, if the input is not in-house.

- xii. For imported input steel, landed cost at Indian port with break-up of CIF value, duties & taxes, port handling charges and inland freight cost.

For and on behalf of _____(Name of firm/entity)

Authorized signatory (To be duly authorized by the Board of Directors)

<Insert Name, Designation and Contact No.>